

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –113/2021

रंजु देवी उर्फ रंजु कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	<p>यह पुनरीक्षण/अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वैशाली के वाद संख्या–21/2021 में दिनांक–11.10.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है ।</p> <p>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को पोषणीयता के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्नगत वाद में सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका–2016 के आधार पर विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है। वाद अभिलेख के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आवेदिका (रंजु देवी) द्वारा सेविका पद के लिए आवेदन करने की तिथि 09.10.2018 है अर्थात् 2019 से पूर्व में है।</p> <p>विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।</p> <p>आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में सेविका का चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2016 से संबंधित है। समेकित बाल विकास सेवाएं</p>	

(आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में वैसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि *“जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।”* प्रश्नगत मामले में पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त